माननीय न्यायमूर्ति एम. एम. कुमार और जितेंद्र चौहान के समक्ष

भारतीय संघ, याचिकाकर्ता

बनाम

धीरज गुप्ता और अन्य,-प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपी. 2008 की संख्या 11890

24 मई, 2010

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - प्रादेशिक क्षेत्राधिकार - जम्मू और कश्मीर कैडर के लिए एक आईएएस अधिकारी का आवंटन - नई दिल्ली में न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती - मामला जम्मू और कश्मीर पीठ को हस्तांतरित किया गया - चंडीगढ़ पीठ जम्मू और कश्मीर राज्य के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए मामले पर निर्णय लेती है - क्या पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पास मामले पर निर्णय लेने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है - नहीं- केवल इसलिए कि कार्रवाई का एक छोटा सा हिस्सा उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ है, यह अपने आप में एक निवारक कारक नहीं हो सकता है, जो उच्च न्यायालय को मामले को गुण-दोष के आधार पर तय करने के लिए बाध्य करता है - याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार सक्षम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए बाध्य किया जाता है।

यह अभिनिर्धारित किया गया है की कि यह निर्विवाद है कि प्रतिवादी धीरज गुप्ता, जो एक आईएएस अधिकारी हैं, को जम्मू-कश्मीर कैडर में आवंटित किया गया था। उन्होंने ट्रिब्यूनल के समक्ष दावा किया है कि जम्मू-कश्मीर को उनका आवंटन नियमों के खिलाफ था और इसलिए, वह हरियाणा कैडर को आवंटित किए जाने के हकदार थे। नई दिल्ली या जम्मू और कश्मीर के न्यायालयों के पास स्वाभाविक रूप से उन क्षेत्रों के भीतर उत्पन्न कार्रवाई के कारण के लिए क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार होगा। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, चण्डीगढ़ पीठ भी जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती है और केवल इसलिए कि कार्रवाई का एक छोटा सा भाग इस न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न हुआ है, जहां तक चंडीगढ़ स्थित अधिकरण द्वारा आदेश पारित किया गया है, यह अपने आप में बाधक कारक नहीं हो सकता है, जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को गुण-दोष के आधार पर मामले का निर्णय करने के लिए बाध्य करता है।

(Para 6)

यह अभिनिर्धारित किया गया है की, उच्च न्यायालय का बाध्यकारी अधिकार अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से परे विस्तारित नहीं होता है क्योंकि एक उच्च न्यायालय का निर्णय दूसरे उच्च न्यायालय या उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के लिए बाध्यकारी मिसाल नहीं होगा। यदि कोई ट्रिब्यूनल तीन उच्च न्यायालयों के बीच विभाजित क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सभी तीन उच्च न्यायालय क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्राप्त करते हैं। इससे न्यायिक अराजकता पैदा होगी। यह फोरम शॉपिंग को भी जन्म देगा।

(Para 7)

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट एएस ग्रेवाल।

वरिष्ठ अधिवक्ता धरम वीर शर्मा और सुश्री ममता रानी, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 1 के लिए।

प्रतिवादी नंबर 4 के वकील बीबी शर्मा।

माननीय न्यायमूर्ति एम. एम. कुमार

1. भारत संघ ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग किया है, जिसमें चंडीगढ़ में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, (जम्मू और कश्मीर सर्किट) चंडीगढ़ पीठ द्वारा पारित 13 सितंबर, 2007 (पी-एल) के आदेश को चुनौती दी गई है। प्रारंभ में, यह देखा जा सकता है कि इससे पहले 9 जुलाई, 2004 को अधिकरण के

न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों के बीच मतभेद उभर कर सामने आए थे। तदनुसार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 26 के तहत, सक्षम प्राधिकारी ने तीसरे सदस्य होने के नाते मामले को उपाध्यक्ष के समक्ष रखा था, यह उपाध्यक्ष है जिसने आक्षेपित आदेश पारित किया है, जो इस न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय है।

2. संक्षेप में, निजी प्रतिवादी धीरज गुप्ता ने जम्मू और कश्मीर कैडर में आईएएस अधिकारी के रूप में अपने आवंटन के संबंध में विवाद उठाया है। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा, 1992 के लिए तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर हरियाणा कैडर को 'अंदरूनी' उम्मीदवार के रूप में दावा किया है। वह ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में सीनियर नंबर 12 पर थे और हरियाणा राज्य में टॉपर थे, जो उनका गृह राज्य है। इसलिए, उन्होंने 'अंदरूनी' या हिमाचल प्रदेश के विकल्प के रूप में हरियाणा कैडर को आवंटन का दावा किया। न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा है कि वह हरियाणा कैडर में आवंटन के हकदार हैं। जम्मू-कश्मीर के लिए उनका आवंटन रद्द कर दिया गया है। हरियाणा को आवंटन के बाद भी उन्हें अखिल भारतीय मेरिट सूची में उनकी मूल वरिष्ठता का हकदार माना गया है क्योंकि उन्हें गलत तरीके से जम्मू और कश्मीर कैडर में आवंटित किया गया था।
3. प्रतिवादी संख्या 1 धीरज गुप्ता के वकील श्री डी. वी. शन्ना ने शुरू में ही गंभीर प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए आग्रह किया है कि इस उच्च न्यायालय को इस मामले पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है। वकील के अनुसार, निजी प्रतिवादी धीरज गुप्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष ओए दायर किया था और बाद में उन्होंने इसे जम्मू-कश्मीर पीठ को स्थानांतरित कर दिया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि निजी प्रतिवादी धीरज गुप्ता को जम्मू-कश्मीर कैडर में आवंटित किया गया है और केवल इसलिए कि चंडीगढ़ में ट्रिब्यूनल की बेंच ने जम्मू और कश्मीर राज्य पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय वास्तव में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र हासिल नहीं करेगा, खासकर जब जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय है जो अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकता है।

उन्होंने कुसुम इंगोट्स एंड अल्लोव्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है और प्रस्तुत किया है कि भले ही कार्रवाई का एक छोटा सा हिस्सा उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ हो, लेकिन इसे अपने आप में उच्च न्यायालय को गुण-दोष के आधार पर मामले का निर्णय करने के लिए मजबूर करने वाला कारक नहीं माना जा सकता है। निर्णय के पैरा 30 में की गई टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए, श्री डी. वी. शर्मा ने प्रस्तुत किया है कि उचित मामलों में, न्यायालय 'फोरम कन्वेन्स' के सिद्धांत को लागू करके अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से इनकार कर सकता है। '

(l) (2004) 6 एस.सी.सी. 254

4. निजी प्रतिवादी धीरज गुप्ता के वकील डी. वी. शर्मा ने इसी मुद्दे पर जोर देने के लिए अंबिका इंडस्ट्रीज बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पैरा 13 और 38 पर भी भरोसा किया है।
5. याचिकाकर्ता के वकील श्री एएस ग्रेवाल ने हालांकि जोरदार तर्क दिया है कि एक बार इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्रवाई का कारण उत्पन्न हो गया है, तो यह आवश्यक नहीं है कि मामले को किसी अन्य न्यायालय द्वारा केवल इसलिए तय किया जाए क्योंकि दूसरी अदालत के पास पार्टियों के बीच विवाद पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र भी है। अपने रुख को पुष्ट करने के लिए श्री ग्रेवाल ने मावर (एचके) लिमिटेड बनाम मालिकऔर पक्षकार पोत एमवी फॉर्च्यून एक्सप्रेस, (3) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के पैरा 29 और 30 पर भरोसा किया है। उन्होंने तर्क दिया कि एक बार जब इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्रवाई का एक हिस्सा उत्पन्न हो जाता है, तो इस न्यायालय के लिए पार्टियों के बीच विवाद का फैसला करना अनिवार्य है। उन्होंने मैसर्स न्यू होराइजन

लिमिटेड बनाम भारत संघ (4) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले पर भी भरोसा जताया है। याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ऐसे मामले में अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया है, जहां हैदराबाद टेलीकॉम के महाप्रबंधक द्वारा टेलीफोन निर्देशिकाओं के मुद्रण और आपूर्ति के लिए निविदा नोटिस प्रकाशित किया गया था, केवल इसलिए कि भारत संघ और संचार मंत्रालय दिल्ली में थे।

6. पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि यह उचित और अनुकूल होगा, अगर विवाद का फैसला जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। यह निर्विवाद है कि प्रतिवादी- धीरज गुप्ता, जो एक आईएएस अधिकारी हैं, को जम्मू-कश्मीर कैडर में आवंटित किया गया था। उन्होंने न्यायाधिकरण के समक्ष दावा किया है कि जम्मू-कश्मीर को उनका आवंटन नियमों के खिलाफ था और इसलिए, वह हरियाणा कैडर को आवंटित किए जाने के हकदार थे। नई दिल्ली या जम्मू-कश्मीर की अदालतों के पास स्वाभाविक रूप से क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र होगा क्योंकि उन क्षेत्रों के भीतर कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, चण्डीगढ़ पीठ भी जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती है और केवल इसलिए कि कार्रवाई का एक छोटा सा भाग इस न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न हुआ है, जहां तक चंडीगढ़ स्थित अधिकरण द्वारा आदेश पारित किया गया है, यह अपने आप में बाधक कारक नहीं हो सकता है, जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को गुण-दोष के आधार पर मामले का निर्णय करने के लिए बाध्य करता है। इस तरह के दृष्टिकोण के लिए तर्कसंगतता माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंबिका इंडस्ट्रीज (सुप्रा) के मामले में निर्णय के पैरा 1 3 और 38 में प्रदान की गई है जो निम्नानुसार है:

> "13. ट्रिब्यूनल, जैसा कि पहले देखा गया है, सभी तीन राज्यों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। तीनों राज्यों में तीन उच्च न्यायालय हैं। यदि पीड़ित व्यक्ति को दोषी माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप, वह एक या दूसरे उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने का चुनाव करता है, तो उच्च न्यायालय का निर्णय केवल उन अधिकारियों पर बाध्यकारी होगा जो इसके अधिकार क्षेत्र में हैं। यह केवल एक अलग अधिकार क्षेत्र के तहत काम करने वाले अधिकारियों पर प्रेरक मूल्य का होगा। <u>यदि किसी उच्च न्यायालय का बाध्यकारी अधिकार उसके क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से परे</u>

नहीं होता है और एक उच्च न्यायालय का निर्णय उसके क्षेत्रीय क्षेत्र के बाहर अन्य उच्च न्यायालयों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के लिए बाध्यकारी उदाहरण नहीं होगा, तो किसी प्रकार की न्यायिक अराजकता लागू होगी। बंबई में किए गए आकलन के आदेश से प्रभावित कोई भी करदाता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर उसके द्वारा निर्धारित कानून का लाभ उठा सकता है और जो उसके अनुकूल हो सकता है और इस प्रकार वह बंबई उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून से सफलतापूर्वक बच सकता है।

38. हमने पहले भी देखा है कि यदि उपर्युक्त प्रश्न में उच्च न्यायालय के निर्णय को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाता है, तो इससे विसंगति पैदा होगी। यह फोरम शॉपिंग की समस्या को भी जन्म देगा। हम यह दिखाने के लिए कुछ उदाहरण देख सकते हैं कि ट्रिब्यूनल के स्थानों के आधार पर अपीलीय मंच के निर्धारण से एनामोलस परिणाम प्राप्त होंगे। उदाहरण के लिए, बॉम्बे में एक मूल्यांकन आदेश से प्रभावित एक करदाता दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके उसके द्वारा निर्धारित कानून का लाभ उठा सकता है जो बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णयों के विपरीत हो सकता है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

7. उपरोक्त पैरा के अवलोकन से विभिन्न कारण सामने आते हैं जो वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होते हैं। उच्च न्यायालय का बाध्यकारी अधिकार उसके क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से परे नहीं है क्योंकि एक उच्च न्यायालय का निर्णय दूसरे उच्च न्यायालय या उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के लिए बाध्यकारी मिसाल नहीं होगा। यदि कोई ट्रिब्यूनल तीन उच्च न्यायालयों के बीच विभाजित क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सभी तीन उच्च न्यायालय क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्राप्त करते हैं। इससे न्यायिक अराजकता पैदा होगी। यह फोरम शॉपिंग को भी जन्म देगा। इसी तरह, कुसुम इंगोट्स एंड एलॉयज लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में दिए गए फैसले के पैरा 30 में अन्य कारण दिए गए हैं। तर्क यह दिया गया है कि उचित मामलों में उच्च न्यायालय 'फोरम कन्वेन्स' के सिद्धांत को लागू करके अपने

विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से इनकार करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होगा। उपर्युक्त पैरा 30 इस प्रकार है -

> "30. तथापि, हमें स्वयं को यह याद दिलाना चाहिए कि यदि कार्रवाई का एक छोटा सा हिस्सा भी उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होता है, तो भी इसे अपने आप में उच्च न्यायालय को गुण-दोष के आधार पर मामले का निर्णय करने के लिए बाध्य करने वाला कारक नहीं माना जा सकता है। उचित मामलों में, न्यायालय फोरम कन्वेन्स के सिद्धांत को लागू करके अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से इनकार कर सकता है।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय के अन्य निर्णय, जिन पर श्री ए एस ग्रेवाल द्वारा भरोसा किया गया है, पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उन निर्णयों में कानून का कोई भिन्न सिद्धांत निर्धारित नहीं किया गया है। मयार (एचके) लिमिटेड (सुप्रा) में फैसले के पैरा 29 और 32 में संक्षेप में कहा गया है कि व्यवसाय का मुख्य स्थान वह होगा जहां निगम की शासी शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसे आमतौर पर तंत्रिका केंद्र के रूप में देखा जा सकता है। उपरोक्त विचारों की अभिव्यक्ति से, श्री ग्रेवाल का तर्क यह प्रतीत होता है कि एक बार जब केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का चंडीगढ़ में अपना मुख्य कार्यालय हो जाता है, तो इसे व्यवसाय के प्रमुख स्थान के रूप में माना जाना चाहिए और जम्मू और कश्मीर राज्य पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के साथ कपड़े पहनाए जाने चाहिए। हमें डर है कि उपरोक्त प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण पहलू को खो देता है, अर्थात्, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश आमतौर पर अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर चलता है और उससे परे नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत न्यायालयों और अधिकरणों के लिए भी बाध्यकारी हैं। इसलिए, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंबिका इंडस्ट्रीज (सुप्रा) में निर्धारित आदेश की अनदेखी नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, मायर (एचके) लिमिटेड (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से अलग संदर्भ में आगे बढ़ता है और हमारे विचार में इस मामले के तथ्यों

और परिस्थितियों पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए, हमें विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क को अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है।

9. इसी प्रकार, मैसर्स न्यू होराइजन लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ का निर्णय भी वर्तमान मामले के तथ्यों से आकषत नहीं है। उस मामले में हैदराबाद टेलीकॉम के महाप्रबंधक द्वारा टेलीफोन निर्देशिकाओं की छपाई और आपूर्ति के लिए निविदा जारी की गई थी और दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस आधार पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया था कि संचार मंत्रालय दिल्ली में स्थित है। यहां तक कि दिल्ली की खंडपीठ के फैसले के तथ्य पूरी तरह से अलग हैं और वर्तमान मामले के तथ्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। तदनुसार, हम याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की उपरोक्त दलील को खारिज करते हैं।

10. . उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, हम पाते हैं कि इस याचिका में उठाए गए विषय वस्तु पर इस न्यायालय का कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है। तदनुसार, रिट याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार सक्षम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए हटा दिया जाता है।

(11) रिट याचिका का निपटान उपर्युक्त शर्तों में किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा । विश्वास खटक, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) रेवाड़ी, हरियाणा ।